भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5164

24.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

फेम इंडिया योजना

5164. **श्री दीपक अधिकारी (देव):**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण' (फेम इंडिया) योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है और इसकी प्रायोगिक परियोजना की क्या स्थिति है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास तथा पारिस्थितिकी तंत्र संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): जी हां, सरकार ने 'भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण' (फेम इंडिया) स्कीम को दो चरणों अर्थात् चरण-I (01.04.2015 से 31.03.2019) और चरण-II (01.04.2019 से 31.03.2024) में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। इस स्कीम ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में सहायता की है।

(ख): प्रथम चरण (01.04.2015 से 31.03.2019), जिसने एक पायलट परियोजना के रूप में कार्य किया और प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता और बाजार की प्रतिक्रिया का आकलन करने में सहायता की, की कार्यान्वयन स्थिति निम्नानुसार है:

i. लगभग 2.8 लाख इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को 359 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन के साथ समर्थन दिया गया।

ii. सरकार की ओर से लगभग 280 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन के साथ देश के विभिन्न शहरों में 425 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसों को स्वीकृत और तैनात किया गया है।

iii. 43 करोड़ रुपये की लागत से 520 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी गई।

iv. विभिन्न संगठनों/संस्थानों को प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं जैसे परीक्षण अवसंरचना की स्थापना, विद्युतीकृत परिवहन, बैटरी इंजीनियरिंग आदि में उन्नत अनुसंधान के लिए 'उत्कृष्ट सुविधा केंद्र' की स्थापना के लिए लगभग 158 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गईं।

फेम (इंडिया) स्कीम का दूसरा चरण (फेम-II) 11,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 01.04.2019 से 31.03.2024 तक कार्यान्वित किया गया था। इस स्कीम की अवधि के दौरान कुल 16,71,606 इलेक्ट्रिक वाहन समर्थित किए गए(बेचे गए) हैं। इसके अतिरिक्त, 31 जनवरी 2026 तक इस स्कीम के तहत 5,195 ई-बसें तैनात की जा चुकी हैं। फेम-II स्कीम के तहत, 01.01.2026 तक कुल 9,159 ईवी पीसीएस स्थापित किए जा चुके हैं।

(ग): 01.04.2024 से लागू की जा रही पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत प्रौद्योगिकीय, अनुसंधान एवं विकास तथा पारिस्थितिकी तंत्र संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. अनुसंधान एवं विकास को मजबूत करने के लिए परीक्षण एजेंसियों के स्तरोन्नयन हेतु 780 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
ii. प्रमुख शहरों में 14,028 ई-बसों की तैनाती के लिए ₹4,391 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
iii. देशभर में इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना के लिए ₹2,000 करोड़ आवंटित किए गए ।
iv. महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिक वाहन घटकों के स्थानीयकरण को बढ़ावा देने और पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

****